an>

Title: Need to give constitutional powers to the National Commission for Backward Classes.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to specifically draw the attention of the Minister of Social Justice and also the Prime Minister. Today, I would like to raise an issue which concerns 50-60 crore of population of India called the OBCs. बहुत लंबी लड़ाई के बाद उनको सैन्ट्रल गवर्नमैंट में 27 परसेंट रिज़र्वेशन इन एजुकेशनल इंप्लॉयमैंट में दिया। उस एजुकेशनल इंप्लॉयमैंट को लागू करने के लिए, उसको सुपरवाइज़ करने के लिए हमारी सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज़, एन.सी.बी.सी बनाया है। वह शैडयूल्ड कास्ट्स एवं शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ कमीशन जैसा है। वह एन.सी.बी.सी. एक्ट लाए। मगर यह अनफॉर्च्युनेट है। यह जो एन.सी.बी.सी. कमीशन है, उसका एक कमिश्नर है। It is toothless and powerless unlike the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is a long pending demand. आपको भी मालूम है कि in the last Lok Sabha, the Committee for the Welfare of Other Backward Classes had recommended to give constitutional powers to the NCBC. मगर अभी तक नहीं हुआ। पिछले तीन साल से वह त्रिशंकु की तरह लटक रहा है। I would request the Government to grant the constitutional powers to the NCBC so that the aspirations of the 60 crore people of India can be met.